15.31 hrs.

ARMED FORCES (SPECIAL POWERS) REPEAL BILL*

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to repeal the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to repeal the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958."

The motion was adopted.

SHRI CHITTA BASU: Sir, I introduce the Bill.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(AMENDMENT OF ARTICLE 31C, ETC.)

SHRI CHITTA BASU (Barasat): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI CHITTA VASU: Sir, I introduce the Bill.

15.32 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL*

(AMENDMENT OF ARTICLES 101 AND 190)

SHRI K. LAKKAPPA (Tumkur): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill further to amend the Constitution of India."

The motion was adopted.

SHRI K. LAKKAPPA: Sir, I introduce the Bill.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Jethamalani. He is not here.

15.33 hrs.

CONSTITUTION (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

(OMISSION OF ARTICLE 310, ETC.)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further consideration of the Constitution (Amendment) Bill, moved by Shri Bhagat Ram.

Shri O. P. Tyagi was on his legs. He will continue his speech.

श्री ओम प्रकाश त्यागी (बहराइच) : श्री भगत राम ने जो विधेयक रखा है उसका मैं विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसके समर्थन में वक्ताओं ने जो दलीलें दी हैं उन में से प्रमुख एक यह थी कि यह एक्ट अंग्रेजों ने अपने हित के दृष्टिकोण से, अपनी इच्छानुसार अपने व्यक्तियों को नियुक्त करने और उनको हटाने के उद्देश्य से बनाया था। उनका कहना है कि आजादी के बाद इस प्रकार का प्रावधान समाप्त हो जाना चाहिए था। अंग्रेजों ने चाहे जिस दृष्टिकोण से इस प्रकार का एक्ट बनाया हो लेकिन हमारे संविधान निर्माताओं के सामने जब ऐसी बातें आई तो उन्होंने भी उनको ज्यों का त्यों रख लिया और बहुत सी बातें ब्रिटिश कांस्टीट्यूशन और अमरीकन कांस्टीट्यूशन से भी ली और वे ली जो हमारे लिए हितकर थीं। अंग्रेजों ने कोई एक्ट बनाया इसलिए वह बुरा था इससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं मानता हूं कि अंग्रेजों का और हमारा दृष्टि-

---

*Published in Gazette of India Extraordinary Part II, section 2, dated 6-4-79.

[श्री ओम प्रकाश त्यागी]

कोण भिन्न भिन्न हो सकता है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। बन्दूक बनाने वाले ने बन्दूक बनाई। उसने अपने दृष्टिकोण से बनाई। हो सकता है डाका डालने के लिए बनाई हो। लेकिन हम ने उस बन्दूक को स्वीकार किया है तो इस उद्देश्य से ताकि देश की रक्षा हम कर सकें, देश को सुरक्षित रख सकें।

धारा 310 को आप देखें। उस में गवर्नर और प्रेसीडेंट को किसी को हटाने का अधिकार दिया गया है। उस में ऐसा लिखा हुआ है :

"Except as expressly provided by this Constitution, every person who is a member of a defence service or of a civil service of the Union or of an all-India service or holds any post connected with defence or any civil post under the Union, holds office during the pleasure of the President, and every person who is a member of a civil service of a State or holds any civil post under a State holds office during the pleasure of the Governor of the State."

यह जो क्लाज है, धारा है यह अधिकांश में सुरक्षा सेनाओं से सम्बन्धित है, चाहे वह सिविल पोस्ट हो या और कोई महत्वपूर्ण पद हो। उनसे सम्बन्ध रखती है यह धारा लेकिन यह पूर्ण अधिकार नहीं देती है प्रेसीडेंट को या गवर्ननर को। 311 में साथ ही साथ प्रोवीजन किया हुआ है :

"No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges."

यह इसमें सेफगार्ड दिया हुआ है। तो इसके रहते हुए मेरी समझ में नहीं आया कि फिर भय क्या है? 310 की धारा को हटाने की मांग किस लिए की गई है? कुछ केसेज ऐसे होंगे जिनमें कि चार्ज देने की आवश्यकता अनुभव न हो प्रेसीडेंट और गवर्नर को। धारा यही है कि चार्ज दिये जायेंगे, स्पष्टीकरण देने के लिए उनको अवसर दिया जाएगा।

वर्तमान समय में इस धारा को रखना आवश्यक क्यों है? यह प्रश्न हो सकता है जब हम ने मिसा व डी० आई० आर० का विरोध किया जो कि तानाशाही की पावर होती है, फिर इस प्रकार के तानाशाही अधिकार हम सरकार को क्यों देना चाहते हैं? क्यों इस धारा का रहना आवश्यक है? इस बारे में मैं कुछ कहना चाहूंगा। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कुछ लोगों को मेरी बात बुरी लगेगी। भारतवर्ष ही नहीं दुनिया के सभी देश बड़ी शक्तियों के अखाड़े हैं। और तीसरी शक्ति बन रहा है, और यह तीनों बड़ी शक्तियां, अमरीका, रूस और चाइना यह अन्य देशों को अपने दायरे में लाने के लिए बहुत बड़ी धनराशि खर्च कर रहे हैं और हर देश में अपने एजेंट्स भी पैदा कर रहे हैं, हर देश में हैं, यहां भी हैं, चाहे उनको सी0 आई0 ए0 कहिए या और किसी नाम से कहिए। साथ साथ में उन देशों के भी एजन्टस हैं जो हमारे पड़ोसी देश कहे जाते हैं। वह भी हमारी गतिविधियों को देखते हैं। हमारे भी वहां एजन्ट होना स्वाभाविक हो सकता है ताकि पड़ोसी देश की गतिविधियों को ध्यान में रखें। तो सरकार को उन एजेंट्स के बारे में और दूसरे जो ऐंटी सोशल एलीमेंट्स हैं, उनको किस कानून के मातहत रखना चाहिए। एक समस्या आयी कि 10, 10 साल से कुछ लोग जेलों में पड़े हैं और उनको चार्जेज नहीं दिए। क्या बात है? उन में से अधिकांश ऐसे ही लोग हैं जिनके कारण से देश को खतरा है। अब देश में जो हमारी सरकार के विरोध में विद्रोह कर रहे हैं उन को पकड़ा है। "कुछ"

ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो हमारी सर्विसेज में हों। उन अराष्ट्रीय तत्वों के बारे में या इस प्रकार के एजन्टों के बारे में जिनकी लायल्टी हमारे देश के साथ नहीं है, विदेशों के साथ है, ऐसे आदमी को हम अपनी फौज में या महत्वपूर्ण पद पर रखें तो किस तरीके से। चार्जेज कहीं कहीं नहीं भी दिए जा सकते हैं क्योंकि हमने अपने गुप्तचर विभाग के द्वारा मालूम कर लिया कि फलां आदमी डाउटफुल कैरेक्टर का है, उसको महत्वपूर्ण पद पर नहीं रहने दिया जा सकता है। दुश्मनी के साथ अगर किसी को निकाला तो बात समझ में आ सकती है। लेकिन डाउटफुल कैरेक्टर के लोगों को पद से हटाने का जो अधिकार राष्ट्रपति और गवर्नर को दिया गया है यह अधिकार उन को जरूर दिया जाना चाहिए। मैं समझता हूं कि देश की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह धारा अत्यावश्यक है, विशेष रूप से इस लिये कि इस देश में अराष्ट्रीय तत्वों का बहुत बड़ा बोलबाला है और हमारे यहां का जो पोलिटिकल ढांचा है वह बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है उसी प्रकार के एलीमैंट्स के द्वारा मेरी इस बात की जानकारी है कि जहां जिसकी शक्ति ज्यादा है, वहां वह अपने-अपने एजेन्ट्स को, अपने व्यक्तियों को ऊपर ऐसे पदों पर पहुंचाना चाहते हैं जहां से उन्हे फायदा हो। उदाहरण के तौर पर मैं कहना चाहूंगा कि कुछ लोगों का विश्वास प्रजातंत्र में नहीं है, लेकिन वह प्रजातंत्र के ढांचे को अपने उद्देश्य के दृष्टिकोण से प्रयोग कर रहे हैं। उनका विश्वास है कि Power comes through the barrel of gun. उनकी मान्यता है कि पूंजीवादी शासन को प्रजातांत्रिक उपाय से नहीं हटाया जा सकता है, इस लिए उस को हटाने के लिए खूनी क्रांति आवश्यक है। उसके लिए दो चीजें आवश्यक हैं, एक तो सेना में अपने आदमी पहुंच जायें और दूसरे जनता में असंतोष हो।

जनता में असंतोष न हो तो वह चाहते हैं, उसे पैदा किया जाए। जहां कहीं गांव में या और कहीं असंतोष चल रहा हो तो उनकी इच्छा है कि वहां असंतोष पैदा करें। इस देश में ऐसी पार्टियों के द्वारा यूनियनें बनाई हुई हैं और उनके द्वारा जगह-जगह हड़तालें कराई जाती हैं। मुझे आश्चर्य होता है जब बैंकों में और एल0 आई0 सी0 में हड़तालें होती हैं और उस से भी ज्यादा तब जब कि एयर इंडिया में और एयर इंडिया के पाइलैट्स द्वारा हड़तालें होती हैं जो कि हाइएस्ट पेड होते हैं, यहां के मंत्रियों से भी ज्यादा उनकी तनख्वाहें होती हैं। इन यूनियनों की लायलटी देश के साथ नहीं है, उन को इशारा कहीं और से मिलता है कि असंतोष पैदा करो जिससे देश में बहबूदी न आये, असंतोष पैदा हो ताकि वह ग्राऊंड्स हमारे यहां तैयार हो जायें इस तरह के एलीमैंट्स के। मैं पूछना चाहता हूं कि संविधान की कोनसी धारा है, जो अराष्ट्रीय तत्व हैं, सन्देहास्पद जिनकी लायलटी है, उनको कोनसी धारा के अन्तर्गत निपटेंगे, उनके साथ व्यवहार करेंगे। यह धारायें हैं जो शक्ति देती हैं लेकिन यह धारा वे लगाम नहीं है, इस के साथ भी धारा 311 जुड़ी हुई है जिसमें यह है कि उनको हटाने से पहले चार्ज लगायें जायेंगे, उनको एक्सप्लेन करने का मौका दिया जाएगा। इस धारा के रहते कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन धारा 310 की आवश्यकता इस लिए है कि इस से देश के अराष्ट्रीय तत्वों से निपटा जा सकता है। इस लिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

PROF. P. G. MAVALANKAR (Gandhinagar): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I rise to congratulate my friend, Mr. Bhagat Ram for the Bill he has brought not because I want to support him fully. I cannot go to the extent that he wants us to go. But I congratulate him because he has pin-pointed through this Bill one of the most serious problems facing the modern State, particularly, democra-

[Prof. P. G. Mavalankar]

cies. Therefore, I rise to support the substance and spirit underlining the measure that he has brought.

Mr. Deputy Speaker, Sir, he has mentioned in his Statement of Objects and Reasons that this Article 310 which he wants to get rid of is based particularly and solely on the Government of India Act 1935. The trouble is that in drafting our Constitution the then Drafting Committee was largely influenced by the Government of India Act, 1935, including its local phraseology, and on many occasions they found it perhaps convenient to adopt bodily most of the Articles into the new set-up, except those which required verbal changes because of new conditions as a result of Independence.

Sir, the Government of India Act, 1935 is writ large in our constitution. This gives me a chance to make the point that if and when this Constitution is going to be amended in a comprehensive way, not with a view to making it more undemocratic but to making it more democratic and workable—then we must apply our mind to this problem of finding out as to how far the Government of India Act, 1935 need not be bodily copied into the new Constitution. So, I think that that point is well taken.

Then, my next point is this. I make a distinction between what is called 'British influence' and what is called 'colonial influence under the British'. The British were having certain sets of standards during their hey-day when the Sun never set in the Empire! One of them was for their own home consumption—of traditions of liberty, freedom, habeas corpus and all the great traditions beginning from the Magna Carta of 1215 onwards. Then there is the other tradition of irresponsible, unreasonable, unanswerable, unaccountable Governments in various colonial territories. India naturally was in the latter category in those decades. Now what I suggest is this. In order to adopt and adapt—according to our conditions and our temperament and situation,—certain things which were inherently good in the British tradition, we have also unfortunately take in a number of colonial things of the British which were lingering on under the various colonies, including India, when we were dependents of the British. Therefore, I think, Article 311 and many other Articles, give me an opportunity to tell the Government and the House that we should also go into the question and find out how far and to what extent the colonial influence of the British is also incorporated in this provision and so we must get rid of that particular thing. Mr. Deputy Speaker, having said that, I want to tell briefly the House why it is that I support the spirit of the Bill. It is mainly because the article leaves tremendously arbitrary powers in the hands of the executive authority.

Now, my friend, Shri O. P. Tyagi was at pains to explain why it is important and necessary that in the case of the security of the State Government must have power even if it is arbitrary. But he meant it, that is to say, 'arbitrary power to dismiss anyone they like, without assigning any reason'. Because, he said, security of State is involved. Now, Sir, I am with him when he says that the security of the State is involved. But the question is this. Who is to decide this question of the 'security of the State'? And, moreover, how do you define the "pleasure doctrine"? Article 310 talks of the "pleasure doctrine". Article 311 talks about the security of the State. Now, Sir, both are, if I may say so, such wonderfully vague and delightfully inadequate, incomplete phrases that one does not know what exactly is meant by phrases like "pleasure doctrine" and "Security of the State".

I would like to tell my hon. friend Mr. Tyagi that although I agree with

him on the principle of it, the difficulty here is that the line is very thin between arbitrary action used in getting rid of the traitors and arbitrary action used in getting rid of inconvenient people. And quite often, even democratic Governments all over the world have used this arbitrary power to get rid of inconvenient people and inconvenient situation under the name of 'security of the State' and 'pleasure doctrine'. That is where the difficulty comes. One can say that not only was this arbitrary power used extensively for a period of these thirty years by various governments at various levels, at the State's level and at the Federal level, but what is worse is, during the Emergency, this particular article was used with such xest and almost with such vengeance that literally almost hundreds of Government servants at all levels were sent home and there was no question of any appeal.

I ask one question whether it is in consonance with what is called natural justice and natural rights of every citizen.

I can understand that there may be exceptional cases where it may be difficult for the State to establish the evil things or the mischievous things or the anti-national activities of a particular citizen. In such cases the citizens may be got rid of, but such cases may be limited in number. They may be exceptional. But the exceptional cases are treated on par with other cases. The Government uses this power to get rid of any one they don't like. And, Sir, I hope you know and the House knows that the President's pleasure or the Governor's pleasure does not mean Mr. Sanjiva Reddy's pleasure or Mrs. Sharda Mukherjee's pleasure in my State. It means the pleasure of a senior Government official, dealing with a subordinate government official. That is what it comes to. And therefore, if that is so, I want to go quickly to Articles 310 and 311. Now, I am not sure whether Articles 310 and 311 bodily should go. Article 310 does mention this; the very first sentence says 'Except as expressly provided by this Constitution'; which obviously means that Article 311 is covered. Art. 310 is subject to Art. 311, because the dismissal or removal of a servant is subject to the procedure laid down in Art. 311 plus these words 'except as expressly provided by the Constitution'. These words also refer *inter-alia* to Articles 124, 148, 217, 218 and 324 which relate to the offices of people like the Supreme Court Judges, High Court Judges, Comptroller and Auditor General, Election Commissioner and so on, and they cannot be removed. There is a special provision laid down due to which they cannot be removed, not by arbitrariness. But the point is that barring these high-placed officers, a large number of other Government officers can be removed by taking advantage of and recourse to Article 310. That is where the mischief enters and it is done in the name of an innocent article 311. Mr. Deputy-Speaker, Sir, Article 311 Clause (2) sub-clauses (b) and (c) mention very interesting points. Sub-Clause (a) is all right which says:

> "(c) where a person is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge; or..."

He must know that is obvious.

Now Article 311(2)(b) says if the superior officer finds that the subordinate should be removed, but it is not reasonably practicable to hold such enquiry, all that the Article says is: 'let him write down on a piece of paper why it is not necessary and the man can be sent home, I think this is a doubtful proposition which is included in the Constitution, particularly under Article 311(2)(b), and (2)(c) is still worse. It says:

> "(c) where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to hold such inquiry."

[Prof P. G. Mavalankar]

I may submit that this is a very wide blanket provision and under this provision, a number of people can be disposed of merely by saying 'No argument, no appeal and the only thing is that you are a security risk for the State and it is better for you to go home'.

Now, it is all right as Shri O. P. Tyagi said: that some strikes are wrong and bad and I agree with him. But in order to get rid of bad things and bad strikers, will you empower the Government with blanket arbitrary powers and thereby deny justice to people who are genuinely aggrieved, whose natural rights and justice and freedoms are denied. That is a moot question which they may ask, and which I do ask! Therefore, I suggest that these Articles need a suitable amendment, rather than get rid of the whole of Articles 310 and 311. That is what I am suggesting.

Mr. Bhagat Ram's statement has mentioned about the Emergency. What happened during Emergency? As I said, hundreds of cases were summarily dealt with and during the Emergency by 44th Constitutional Amendment; later on it became 42nd Amendment; the Government at that time got rid of judicial review over service rules and conditions and introduced Administrative Tribunals. The new Janata Government came to power and brought in a Constitutional Amendment to change it and rectify it and yet they could not do it because the Administrative Tribunals still remain. After all, they may consist of broadly Government servants—Senior Government servants and retired Government servants comprising the tribunals—they decided whether it was rightly punished or wrongly punished. I think that of course is a lacuna which we must go into and at the earliest opportunity we must get rid of the administrative tribunals and bring back and restore judicial review for the benefit of the natural rights and freedoms of the citizens and Government servants.

I have two more points to make. One is that I would suggest in regard to Article 311 which lays down the procedure, that the procedure is so straitjacketed that once the procedure is followed by the Government which means by any Senior Government officer or superior Government officer, then I am afraid—as far as my reading goes, I admit that I am not a lawyer, I am subject to correction by my lawyer friends here—that my reading of the Article shows to me that once Article 311 is satisfied in terms of procedure satisfactorily implemented, then neither the Supreme Court nor any High Court can go into the question of finding out whether the Government servant was removed rightly or wrongly. Is that right? Can you leave the Supreme Court and the High Court completely to the mercy of some formula in compliance with the provisions of Article 311, particularly Clause (2)(a) and (b) and more particularly (2)(c), if not 2(a)? The whole subject of service rules requires to be looked into more carefully. I know, Article 309 is an enabling Article, it does not say that the State Legislatures and the Indian Parliament must make laws for service rules; of course, the Government is not obliged to do that; it is only an enabling provision. And as far as my information goes, no State Legislature or the Indian Parliament have made any laws regarding service rules. Let them correct me, if I am wrong. If that is so, then the matter becomes all the more serious because of the situation. I do not know for instance, whether the service rules of the employees of our Secretariat, Lok Sabha and the other House, are according to the procedures well laid down by democratic countries. At least as a Member of Parliament, I do not know what those service rules

are. These have not been placed on the Table of the House. An element of arbitrariness is, therefore, there in these matters. If that has to be removed, if you want the morale of the public services to be retained, morale in terms of integrity, permanence, impartiality and incorruptibility of the civil services to be retained, then I think, a lot needs to be done in terms of finding out what exactly the phatse 'security of the State' is and getting rid of it as being use as the blanket provision and blank provision in the name of the security of the State. Even the 'pleasure doctrine' needs to be suitably defined and amended. If that is done, the purpose of my hon. friend in bringing forward this Bill will be more than adequately met.

श्री कंवरलाल गुप्त (दिल्ली सदर) : उपाध्यक्ष जी, इस विधेयक में जो विधान के संशोधन की बात कही गई है और जिस भावना से यह विधेयक सदन के सामने लाया गया है उसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं। यह तो सभी स्वीकार करेंगे कि जो भी लोग नौकरी में हैं उनको सिक्योरिटी होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जहां काम करता है वहां वह अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा लगा देता है और अगर किसी भी समय उससे कह दिया जाये कि आप चले जायें तो शायद उसका ही नहीं, उसके परिवार का भी बरबाद हो जायेगा। सिक्योरिटी आफ सर्विस रहनी चाहिए। इसमें कहीं भी दो राय नहीं हैं। यह भी सही है कि इमरजेन्सी के दिनों में हमने देखा कि एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों अधिकारी जोकि उस समय के राजनीतिक नेताओं को पसन्द नहीं थे, उनको उठाकर के बाहर फेंक दिया गया इसी बात की वजह, या अगर कोई बड़ा अधिकारी अपने छोटे से नाराज था तो उसको भी केस बनाकर के बन्द कर दिया गया और हमेशा के लिए ऐसे लोगों का जीवन बर्बाद हो गया, उनके परिवारों का जीवन बर्बाद हो गया। ऐसे उदाहरण एक नहीं, अनेकों इमरजेन्सी में आए हैं। शायद इसी भावना से प्रेरित हो हो कर मेरे मित्र ने यह संशोधन यहां पर रखा है। मैं इसकी कद्र करता हूं लेकिन इस तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जिसको हमें ओझल नहीं करना चाहिए। उसका थोड़ा सा दिग्दर्शन अभी हमारे त्यागी जी ने किया है। क्या यह बात सही नहीं है कि अभी रूस के कुछ अधिकारी जोकि रशियन इम्बैसी में काम करते थे वे हमारे कि सं. सरकारी कर्मचारी से मिल करके सरकार की बहुत सारी खुफिया बातें विदेशों को देते थे? इस तरह की यह कोई पहली घटना नहीं है, इस तरह की कई घटनायें पहले भी हमारे देश में हुई हैं, सम्बन्धित सरकारी कर्मचारियों को गिरफ्तार भी किया गया है, उनकी सजा भी हैं। कई हुई बार ऐसा भी हो सकता है कि तरह क इस जो डाउटफुल करैक्टर हैं उनके ऊपर केस नहीं चलाए जा सकते।

16.00 hrs.

मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, क्योंकि मुकदमा चलाने के लिये, कन्विक्शन कराने के लिये काफी एविडेन्स, डाक्यूमेन्ट्री एविडेंस सब कुछ चाहियें। लेकिन किसी का डैंजरस करैक्टर हो, डाउटफुल करक्टर हो, सरकार को यह लगता हो कि इस का यहां पर रहना ठीक नहीं है, ऐसी सूरत में सरकार क्या करे? इस का जवाब श्री भगतराम जी ने नहीं दिया है। मैं समझता हूं — इस के लिये यह जरूरी है कि ऐसे लोगों को बर्खास्तगी के भी छुट्टी देने की जरूरत हो, तो सरकार को देना चाहिये। क्योंकि यह सदन या बाहर की जनता इस तरह से अगर देश की सिक्योरिटी को खतरे में डाल देंगे, तब फिर कोई काम नहीं चलेगा। देश की सिक्योरिटी सब से जरूरी चीज है।

[श्री कंवर लाल गुप्त]

यह विधान हमारे देश के नेताओं ने बनाया, लेकिन केवल विधान बनाने से तो काम नहीं चल सकता, विधान तो एक किस्म की गाइड लाइन है, और पीछे उस के तोड़ने मरोड़ने का काम भी हुआ है। इसी विधान के नीचे 1975 में क्या इन्दिरा गांधी डिक्टेटर नहीं बनी ? उस ने विधान का कई दृष्टियों से उलंघन किया, विधान का संशोधन करके विधान के तहत——I think she was the first constitutional dictator in this country and the worst dictator ever produced in this country.

यह सब क्यों हुआ ? असल में विधान पर अमल करने वाली सरकार कैसी है — बहुत कुछ उस पर निर्भर रहता है, न कि इस बात पर कि विधान में क्या लिखा हुआ है। मैं आप को विश्वास दिलाना चाहता हूं—जनता पार्टी की सरकार रूल आफ ला में विश्वास करती है, जनता पार्टी कानून में विश्वास करती है। जनता पार्टी चाहती है कि हर आदमी को न्याय मिले। मैं मानता हूं—जनता पार्टी में दसियों बुराइयां होंगी हम आपस में लड़ते भी हैं, लेकिन एक चीज के लिये जनता पार्टी को दोषी नहीं कहा जा सकता —पिछले दो वर्षों में जनता पार्टी में किसी को जान बूझ कर दुश्मनी के नाते तंग किया हो। ऐसा कम से कम एक केस भी अभ्र में मेरी निगाह में नहीं आया। जनता पार्टी न्याय और कानून दोनों की कद्र करती है। यह शिकायत तो बहुत बार जनता ने की जनता पार्टी जितनी सख्त होना चाहिये गृह मंत्रालय जितना सख्त होना चाहिए — उतनी सख्त नहीं है। लेकिन यह कोई नहीं कहता कि किसी इनोसेंट आदमी को पकड़ कर जनता पार्टी ने बन्द कर दिया हो या किसी सरकारी कर्मचारी को, जिसे नहीं हटाना चाहिये था, उठा कर फेंक दिया हो या उस को हटाने में इस धारा का इस्तेमाल किया हो। क्योंकि जनता पार्टी का काम करने एक तरीका है, सोचने एक अलग तरीका है, जनता सरकार जिस आधार पर बनी है, उस आधार के नाते मैं यह कह सकता हूं कि इस संशोधन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हां, यह हो सकता है कि कल को कोई दूसरी सरकार आये और वह इस का दुरुपयोग करे तो यह जो ब्लांकेट पावर है, यह सरकार को देना ठीक नहीं होगा, उसी दृष्टि से यदि सरकार कोई री-थिंकिंग करना चाहे तो ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन जब तक जनता पार्टी है — मेरा विश्वास है वह इस तरह का काम नही करेगी।

लेकिन जहां तक डिफेंस का सवाल है, देश की सिक्योरिटी का सवाल है — आप को याद होगा— संजय गांधी को हम कई बार यहां क्रिटिसाइज करते हैं और देश में जो अत्याचार हुआ उस के लिये बहुत हद तक हम उस को भी दोषी मानते हैं, लेकिन एक बात जो उस ने अच्छी की, उस का मैं सब के सामने कन्फेशन करता हूं, एमर्जेन्सी के दिनों में इस देश में कुछ ऐसे तत्व थे जो कांस्टीट्यूशनल तरीके में विश्वास नहीं करते थे।

16.05 hrs.

[SHRI N. K. SHEJWALKER *in the chair*]

जिन का तीर्थ स्थान भारत में नहीं है दूसरी जगह पर है और जो आदेश दूसरी जगह से लेते हैं वे लोग छा रहे थे सरकार के ऊपर। यहां तक कि उनके नेताओं ने भी कह दिया था कि सैंटर में भी हमारी कोएलिशन सरकार बनेगी। इंदिरा गांधी की सरकार भी उनके पीछे पीछे और साथ साथ चलती थी। यही एक संजय गांधी थे जिस का मैं कांट्रीब्यूशन बता रहा हूं जिसने इस बात का विरोध किया

और उसको एक्सपोज किया और इतने जोर से किया कि बेटे के साथ मां को भी खुल कर संजय गांधी के हक कहना पड़ा। जिस तरफ वह सरकार जा रही थी उस तरफ जाने से रुक गई और समाज विरोधी तत्व जिन के हाथ में सरकार जाती तब और भी ज्यादा जो अत्याचार होते और देश का क्या होता, मैं नहीं कह सकता। शायद जितना हुआ उससे और भी ज्यादा बुरा होता। उस चीज को संजय गांधी ने रोका। यह बहुत बड़ा कांट्रीब्यूशन संजय गांधी का था। इसको मैं पब्लिकली स्वीकार करता हूं।

जो भी आप निर्णय सर्विसिस के बारे में लें आपको देखना चाहिये कि क्राइसिस आफ कान्फिडेंस पैदा न हो। विश्वास सरकार का बना रहना चाहिये और सरकार में बना रहना चाहिये। आज सरकारी कर्मचारी हड़ताल करते हैं। बैंकों के लोग करते हैं। चपड़ासी जिन को पांच सौ रुपया महावार मिलता है वे करते हैं बैंक के अफसर करते हैं। पहली बार 30–32 साल की हिस्ट्री में यह जनता पार्टी की सरकार में हुआ है और उसने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। जिन कर्मचारियों को दो सौ रुपया मिलता है वे तो हड़ताल नहीं करते हैं, जो खेती हर मजदूर हैं और जिन को चार पांच रुपया रोज मिलता है वे नहीं करते हैं, उनके लिए कोई बोलता नहीं है लेकिन जिस चपड़ासी को पांच सौ रुपया मिलता है वह हड़ताल करता है, जिस अफसर को ढाई हजार मिलता है वह करता है और यह सरकार बैठी रहती है इसको देखना चाहिये।

मैं यह स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सरकारी कर्मचारियों को हड़ताल नहीं करनी चाहिये। यह मेरी निजी राय है। आप इससे सहमत नहीं होंगे यह मैं जानता हूं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एकतरफा किसी होती जाए। कोई मशीनरी ऐसी होनी चाहिये जो इंडिपेंडेंट हो जिस के पास कर्मचारी और सरकार दोनों जा सकें और अपना अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकें और उसका जो निर्णय हो वह सब को मान्य होना चाहिये। हड़ताल को खत्म करना चाहिये। मैं बहुत ज्यादा ट्रेड यूनियनिज्म सरकारी कर्मचारियों की पसन्द नहीं करता हूं। हड़ताल को भी पसन्द नहीं करता। लेकिन इस तरह की मशीनरी अवश्य होनी चाहिये जिस का फैसला दोनों पक्षों को मान्य हो।

मैं और अधिक न कहते हुए इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस विधेयक की भावना की कद्र करता हूं लेकिन जनता पार्टी के राज्य में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि जनता पार्टी रूल आफ ला में विश्वास करती है, कानून में विश्वास करती है और दो साल में ऐसा कोई भी केस नहीं हुआ है जहां जनता पार्टी ने किसी भी आदमी को गलत तरीके से फंसाया हो। किसी सरकारी कर्मचारी को डिसमिस किया हो। इसलिये कोई इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन कल को यह सरकार बदल सकती है क्योंकि डेमोक्रेसी है, अतः उसके लिये कोई न कोई रास्ता ऐसा निकालना चाहिये जिसमें इस तरह जो बदले की भावना से कर्मचारी हटा दिये गये या निकाले जाते हैं उनकी भी देखभाल करने के लिये कोई इंडिपेंडेंट मशीनरी हो।

इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर): सभापति महोदय, जो गैर सरकारी बिल उपस्थित किया गया है संविधान संशोधन के सम्बन्ध में इस पर पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से तर्क आ रहे हैं और अधिकांश वक्ताओं ने इस बात को स्वीकार किया है कि वर्तमान संविधान में जो प्रोवीजन है उसमें संशोधन

[श्री राम विलास पासवान]

की आवश्यकता है। वैसे तो सरकार के यहां मंत्री हैं जो इस पर गहराई से अपने विचार रखेंगे, और सदन की भावना को सरकार तक भी पहुंचायेंगे, फिर भी मैं दो, तीन बातें यहां रखना चाहता हूं। अभी माननीय कंवरलाल गुप्त, श्री ओम प्रकाश त्यागी और माननीय मावलंकर जी जो संविधान के एक्सपर्ट हैं उन्होंने अपने विचार रखे। तो एक बुनियादी चीज है, चाहे जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, सरकार क्या मानती है यह उस पर निर्भर करता है। ऐक्ट ऐक्ट है, लेकिन फैक्ट अलग हो जाते हैं। मैंने उस दिन भी कहा था कि हरिजन की बात ले लिजिये, जो भूमिहीन है सरकारी नियम के मुताबिक जिस जमीन पर वह बसा हुआ है उसको पर्चा मिल जाना चाहिये लेकिन होता क्या है। रात तक अगर घर था और सबेरे में जमीन हो गयी, तो मामला अफसर के पास जाता है। अगर गरीब घर का वह अफसर है तो कहता है कि नहीं कल तो घर था इसलिये इस गरीब को पर्चा दे दो। लेकिन अगर किसी बड़े घराने का अफसर हो तो वह कहेगा कि घर था ही नहीं इसलिये अगर पर्चा मिला भी है तो उसको कैंसिल करो। तो बुनियादी तरीके से हम क्या चाहते हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि जो संविधान की 310 धारा में है उसके मुताबिक राष्ट्रपति के नजदीक कितने लोगों की सुनवाई जाती है? कितने आदमियों के मामले को वह पढ़ते हैं? फिर राष्ट्रपति का नाम क्यों प्रयोग करते हैं। आप कह दीजिये सेक्रेटरी। राष्ट्रपति को क्यों लिखा जाता है जब कि वह किसी को जानता भी नहीं। और सब कुछ होता जाय राष्ट्रपति के नाम पर। मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से अब जनता सरकार बनी है और मैं मानता हूं कि आपने जो लिबर्टी दी है वह जरूरत से ज्यादा दी है जिसके तहत सारी चीज अस्तव्यस्त हो गई है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि कानूनी तरीके से वैधानिक तरीके से आप उसका एक निदान अभी तक नहीं निकालें तो बहुत कम अवसर आते हैं जब आप ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगा सकते थे, बड़े से बड़ा डिक्टेटर भी जो होता है जब तक देश को एक बटे चार जनता या जनमत उसके पीछे नहीं रहता है तो वह डिक्टेटर नहीं बन पाता है। इस देश में मेरी राय में तीन बार मौके आये जब आप लगाम लगा सकते थे नौकरशाही पर। एक बार जब हम आजाद हुए और पंडित नेहरू प्रधान मंत्री बने, अपार जनसमूह उनके पीछे था। और उस समय यदि हम कानून के द्वारा कोई ऐसी लगाम लाते, तो निश्चित रूप से इस देश में जो अफसरशाही, नौकरशाही का बोलबाला है, उस पर हम लगाम लगा सकते थे।

दूसरा मौका 1971 के चुनाव के बाद आया, जिस समय श्रीमती इन्दिरा गांधी इस देश की प्रधान मंत्री थीं और उन के पीछे उस समय एक जनमत आया था अगर वह चाहती तो इसकी लगाम लगा सकती थीं।

तीसरा मौका आया 1977 के चुनाव के बाद जिसमें इस देश के प्रधान मंत्री श्री मोरारजी भाई बने और देश की बागडोर जनता सरकार के हाथ में आई। लेकिन इन 2 साल के बाद, स्वयं मंत्री जी भी इस बात से सहमत होंगे कि हमने इस अवसर को खोया है। अभी भी हमारे राज्य में अफसरशाही पर हमारी लगाम नहीं रही है। आज भी जो सस्पेंड और डिस्चार्ज करने की बात कहते हैं, मैं जानना चाहता हूं कि कितने आई० ए० एस० और कितने आई० पी० एस० अफसरों को आपने डिस्चार्ज किया है, कितनों की सेवाएं खत्म होती हैं? ... एक गिरोह बना हुआ है।

पुलिस का बड़े-से-बड़ा अफसर आई० पी० एस० होगा, उससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं है । सिविल सर्विस का बड़े-से-बड़ा अधिकारी आ० ए ० एस० होगा । जैसा कि होम मिनिस्ट्री की डिबेट में कहा गया है जब इंटरव्यू में लिख देते हैं कि इस परिवार का कोई आदमी आई० ए० एस० या आई० पी० एस० में रहा है या नहीं, तो जब इंटरव्यू में यह सारी बात चलती है तो जब किसी अधिकारी के खिलाफ किसी जांच को बैठाने की मांग हम करते है, तो वह किसके पास जाती है ? आई० ए० एस० अफसर की शिकायत आई० ए० एस० के पास जाती है, आई० पी० एस० की शिकायत आई० पी० एस० के पास जाती है और किसी के पास नहीं जाती है । इन लोगों की एक एसोसियेशन बनी हुई है उसमें यह तय है कि जब भी इस तरह का कोई मामला आवे तो उसे इस तरह से रफा दफा कर दो कि उसके खिलाफ कुछ न हो सके । न तो मंत्री को फाइल देखने की फुरसत है और न उनकी नीयत साफ है । यदि कहीं पर नीयत साफ है तो नीति साफ नहीं है, कहीं नीति साफ है तो नीयत साफ नहीं है, कहीं दोनों चीजें हैं तो वहां बोल्डनेस नहीं है कि एक्शन लिया जा सके । नतीजा यह होता है कि आजादी के बाद यदि आप देखेंगे परसैंटेज लगायेंगे तो ऐसे मामलों में 00 और .00 परसैंटेज निकलती है । इसमें देखा जाये कि किसी भी आई० ए० एस० और आई० पी० एस० को दंडित किया गया है या नहीं ।

हम लोग एमर्जेन्सी के समय में थे, जयप्रकाश जी के ऊपर क्या मेन मुद्दा था ? इन्दिरा गांधी के द्वारा यही तो प्रचार किया जाता था कि जयप्रकाश नारायण फौज को बगावत करने के लिए कह रहे हैं । सिविल सर्विस के लोगों को बागी बना रहे हैं । कहते हैं कि सरकार के गलत आदेश को मत मानो ।

आज हम सरकार में हैं तो आज हमको यूनियनबाजी बहुत बुरी लग सकती है, अगर कोई हमारे खिलाफ मुरदाबाद के नारे लगाये तो हम सह नहीं सकते । अगर कोई प्रदर्शन होता है तो लगता है जैसे कलेजे में चोट लगती है । लेकिन जब कल हम सरकार के बाहर थे और फिर यदि कल सरकार के बाहर आने की बात होगी तो वही हमारा आधार बनता है । इसलिए इस बात को सीधे जड़ से काट देने की बात कि इसका कोई अधिकार रहेगा ही नहीं, तो मैं इससे डिफर करता हूं, एग्री नहीं करता हूं । राइट टु डिफर सबको रहना चाहिये । आप किसी को बिना सुने कुछ नहीं कर सकते । क्रिमिनल भी हैं, डाकू और लुटेरे भी हैं, मर्डर करने वाले भी हैं, लेकिन उनको भी सफीशिएंट मौका दिया गया है कि तुमको भी अपने पक्ष में कहना हो तो कहो । उनको न्यायालय में जाने का हक है । सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों को इस अधिकार से वंचित नहीं करना चाहिये । एमर्जेन्सी के पहले लोगों को कोर्ट में जाने का अधिकार था । उधर तो वही सफीशिएंट था, लेकिन एमर्जेन्सी में उसको कट कर दिया गया और कहा गया कि ट्रिब्यूनल बनायेंगे क्योंकि कोर्ट में जो सरकार चाहे वह नहीं हो सकता है, लेकिन ट्रिब्यूनल में जो सरकार चाहे वह करा सकती है । इसलिए कोर्ट का अधिकार घटा कर ट्रिब्यूनल में ले लिये । क्या हमको मालूम नहीं है कि एमर्जेन्सी में क्या होता था ? अगर कहीं 50 हजार की भीड़ जुटाना हो तो नोटिस चला जाता था कि जितने भी विभाग के कर्मचारी हैं, वह सब फील्ड में पहुंच जायें, इससे 50 हजार की भीड़ तुरन्त इकट्ठी हो जाती थी । अगर कहीं संजय गांधी और इन्दिरा गांधी जाते थे तो इसी तरह से लाखों की भीड़ सरकारी कर्मचारियों द्वारा जुटाई जाती थी । जो सरकारी कर्मचारी कहते थे कि उन्हें नहीं जाना है, तो उन पर तुरन्त नोटिस जारी हो जाता था । हमको यह भी मालूम है कि सरकारी कर्मचारियों और

[श्री राम विलास पासवान]

शिक्षकों को यह कह दिया गया था कि उन्हें एक महीने में तीस व्यक्तियों की नसबन्दी करानी होगी, और अगर वे नहीं करायेंगे, तो दो तीन बार वार्निंग देकर उन्हें निकाल दिया जायेगा । इमरजेंन्सी के दौरान यह सब कुछ हुआ है ।

> जनता पार्टी के घोषणापत्र में कहा गया है कि वह ऐसा प्रबन्ध करेगी कि सरकारी कर्मचारियों का अकारण उत्पीड़न न किया जा सके, उन पर कोई राजनैतिक दबाव न पड़ने पाए और उनको गैर कानूनी आदेश मानने तथा अवैध काम करने के लिए बाध्य न किया जा सके । न्यायालयों का आश्रय लेने का उनका अधिकार उन्हें वापिस मिलेगा ।"

मेरे जैसा आदमी तो यह कहेगा कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी किसी पब्लिक वर्क में ढीले करता है, तो बेशक उसे कड़ी से कड़ी सजा दी जाये । हम लोगों से रोज झगड़ा होता है । रेलों में हम देखते हैं कि अगर कोई गाड़ी दो घंटे लेट हो गई, तो सेक्रेटेरियट के बाबू लोग रेलवे कर्मचारियों को गाली देना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जनता पार्टी की सरकार आई है और गाड़ी दो घंटे तक लेट हो जाती है । हम उनसे कहते हैं कि जब वे अपने दफ्तर में होते हैं और रेलवे कर्मचारी वहां किसी काम से जाते हैं, तो वे स्वयं क्या करते हैं । आज स्थिति यह है कि अगर कोई पोस्टल एम्पलाई रेल पर चढ़ता है, तो वह रेलवे कर्मचारियों को गाली देता है और अगर रेलवे कर्मचारी को पोस्टल विभाग से कोई काम पड़ता है, तो वह उस विभाग के कर्मचारियों को गाली देता है । (व्यवधान)

अगर हम कुछ नहीं करेंगे, तो लोग हमें
गाली देंगे कि हम कुछ नहीं कर पा रहे

गवर्नमेंट एक पावरफुल कमेटी या
बनाये— ऐसी कमेटी नहीं कि उसकी
आते आते दूसरी कमेटी बैठ जाये—, जो
नई व्यवस्था करे—न 1935 का कानू
न विक्टोरिया के राज का कानून रहे
कांग्रेस के राज का कानून रहे—, जिसमें
तय कर दिया जाये कि बिजली.,
डिफेंस आदि जो पब्लिक यूटिलिटी या
साधारण के उपयोग सें सम्बन्धित विभा
यदि उनमें कोई कर्मचारी सुस्ती या लापर
करेगा, तो सरकार उसे कतई बर्दास्त
करेगी, और नियमों के तहत ऐसे कर्म
को कड़े से कड़ा दंड देने की व्यवस्था
सरकार को यह कदम उठाना चाहि
केवल संविधान सें यह लिख देने से कि सर
कर्मचारी राष्ट्रपति की इच्छा, खुशी या
पर ही नौकरी में रहेंगे, अभी तक कोई
नहीं पड़ा है । कहा जाता है कि संविधा
इस अनुच्छेद से सरकारी कर्मचारी भय
हैं । मगर उस अनुच्छेद को पढ़ता कौन
कोई नहीं पढ़ता है ।

अगर कोई सरकारी कर्मचारी
सीनियर बास की इच्छा के मुताबिक
करता है, उसके कहने के मुताबिक
काम भी करता है, तो अनुच्छेद 310
311 के प्रयोग का प्रश्न ही नहीं उठता
यह कहा जा सकता है कि इन अनुच्छे
कारण डिसिप्लिन कायम रहती है या कर्म
अपने बास की हां में हां मिलाने और उ
इच्छा के अनुसार दिन को रात और रात
दिन कहने के लिए बाध्य होते हैं । मगर
जन-साधारण की कोई भलाई होने
नहीं है ।

सेंटर में तीस लाख एम्पलाईज हैं
स्टेट्स में चालीस लाख एम्पलाईज
दूसरी जगह की बात छोड़ दीजिए । हम

पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। पिछले सालों की प्रोसीडिंग्ज को उलटते उलटते पता चला कि 1955 से आठ नौ डिपार्टमेंट्स पर कभी बहस ही नहीं हुई और उनकी डिमांड्ज वैसे ही पास हो जाती रही हैं। हम लोग इस सेक्रेटेरियट में बैठे हुए हैं। हम लोगों ने यह जानने की कोशिश की कि इस सेक्रेटेरियट के एम्पलाईज के लिए क्या नियम और कायदे-कानून बने हुए हैं। उनके लिए कोई नियम आदि नहीं हैं।

इसलिए यह आवश्यक है कि ऐसा कानून बना दिया जाये, जिससे न तो सरकारी कर्मचारी को यह कहने का मौका मिले कि किसी नियम के तहत उस पर ज्यादती की जा रही है, और साथ ही जो कर्मचारी गड़बड़ करे, डीले करे—जस्टिस डीलेड इज जस्टिस डेनाइड—, उसको बचने का मौका भी न मिले, उसको माफ़ भी न किया जाये।

इन दोनों कसौटियों को देखते हुए, एक तरफ जनता और दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों को अननेसेसरिली हैरेस कर ने की प्रवृत्ति, इन दोनों को देखते हुए यदि कोई ठोस उपाय या कदम सरकार निकाल सके तो निकालना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं समाप्त करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

SHRI B. C. KAMBLE (Bombay South-Central): I would like to make a few observations on this Bill. The present position appears to be that all the services are being regulated under the rules which were framed prior to independence. All these rules are being continued under the transitory provisions of the Constitution. Therefore, it is high time that the Government come with a comprehensive Bill in this Parliament, governing the service conditions, and dispense with all the previous rules.

Secondly, this Bill proposes to delete sub-clause (c) of the second proviso. But, so far as article 310 is connerned, I would have been happier if the mover had suggested some substitute provision in place of article 310, because that is controlled by article 311. Therefore, so far as article 310 is concerned, it is not so dangerous as it is being controlled by article 311. So far as defence and other services are concerned, a Bill should be brought here, or at least the present rules should be discussed in the House and approval should be obtained. Otherwise, these rules are going to be very dangerous for the service people.

Even though there is a provision in article 311 that until an enquiry is made, no person shall be either dismissed, removed or reduced in rank, still it is done without an enquiry under the famous rule 5, which says that if a person is temporary, then such an enquiry is not necessary and that will not attract the provisions of article 311. In fact, article 311 is very specific. It says:

> "No person who is a member of a civil service of the Union or an all-India service or a civil service of a State or holds a civil post under the Union or a State shall be dismissed or removed by an authority subordinate to that by which he was appointed.
>
> (2) No such person as aforesaid shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charger...."

This article is superseded by rule 5 and summarily several people have been removed from service without any enquiry being held, which means that rule 5 is given a position or status far superior to that of article 311. I would suggest to Shri Bhagat Ram

[Shri B. C. Kamble]

that along with sub-clause (b), sub-clause (c) should also be deleted, because so long as that enquiry is not there, it is a violation of article 311.

Therefore, I partly support the Bill. At the same time, I would suggest to the hon. Minister to bring all the rules before the House and get approval or bring a comprehensive Bill so that there will be uniformity in all the departments and justice would be done to all the people concerned.

श्री लक्ष्मी नारायण नायक (खजुराहो) : माननीय सभापति जी जो संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत है मैं उसकी भावना की कद्र करता हूं। जब हम प्रजातंत्र को मानते हैं तब फिर हमें उसी तरीके से चलना भी होगा। लोग चाहे सर्विस में हों या सर्विस में न हों, उनके अधिकारों को मानना चाहिए। इतने वर्षों के बाद भी इस देश में आज भी ऐसे आदमी हैं जिनको जिन्दगी निश्चितता की जिन्दगी नहीं है। वे यह समझ नहीं पा रहे हैं कि कल हमारा क्या होगा। इसी तरह से जो सर्विस में हैं अगर उनको भी इतनी गारन्टीज रहे कि कल हमारा भविष्य क्या होगा तो यह उचित नहीं है। इसलिए मैं मानता हूं कि चाहे सर्विस में हों या कहीं भी हों उनसे कारण जरूर पूछा जाना चाहिए कि तुमने ऐसी गलती की है इसलिए इसका जवाब दो—बिना कारण पूछे किसी को भी सर्विस से निकालना उचित नहीं है। हमारी जो मौलिक बातें हैं उन्हें हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने इस बात को कहा है, लोकसभा में भी और बाहर भी—कि हमारा शासन गांधी जी के उसूलों पर चलेगा तो गांधी जी की जो मान्यतायें रही हैं उनके अनुरूप ही हमें प्रगतिशील शासन चलाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि गांधी जी ने हमें क्या आदर्श बताए हैं। इसलिए चाहे सैनिक हों या असैनिक, किसी भी पद पर हों, बिना कारण उनको नहीं निकाला जाना चाहिए।

यहां पर उदाहरण दिया गया कि यहां का कोई जासूस विदेशी जासूस से मिलकर यहां की खबर दे दे तो उससे देश को आघात हो सकता है। इस संबंध में मेरा कहना है कि किसी दूसरे राष्ट्र का या यहां का भी कोई देशद्रोही हमारे देश को तभी नुकसान पहुंचा सकता है जबकि हमारी जनता हमारे साथ न हो। इसलिए हमारा प्रशासन ऐसा होना चाहिए, हमारे कामकाज ऐसे होने चाहिए कि हम अपने देश की जनता को अपने विश्वास में लें। किसी भी शासन का यह प्रथम काम है कि जिस जनता पर शासन करना है उस का विश्वास उसके साथ हो। यदि इस प्रकार की दृढ़ बातें हम कर लेते हैं तो फिर चाहे कोई बाहर की शक्ति हो या यहां की शक्ति हो वह इस देश को और यहां की सरकार को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इसलिए हमें मजबूती के साथ उन मान्यताओं को अमल में लाना होगा। एक ओर तो हम कहते हैं कि हमारा प्रजातंत्र में विश्वास है तो प्रजातंत्र में विपक्षी दल भी होंगे और विपक्षी दल का अधिकार है संगठन करने का, जुलूस निकालने का और मौका पड़े तो हड़ताल भी करने का। गांधीजी ने भी कहा था कि कोई भी सरकार हो, अगर किसी के साथ कोई अन्याय होता है तो उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। कोई हड़ताल भी तभी हो सकती है जब जनता साथ दे। अभी बैंक वालों ने नोटिस दी थी कि हड़ताल करेंगे लेकिन क्या जनता ने उनका साथ दिया? नहीं दिया इसलिए उनकी हड़ताल नहीं हो सकी। इसलिए मैं कहता हूं कि कोई भी कुछ कहता रहे, अगर उसकी बात सही है तभी वह उसमें कामयाब होगा। कुछ लोग मिलकर अगर किसी संस्थान या दफ्तर में किसी तरह से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो वे नहीं पहुंचा सकते हैं कि फिर गुप्तचर विभाग किस लिए है? अगर कोई ऐसी खबर मिलती है तो उस सम्बन्ध में उसको बड़ा प्रबंध रहना चाहिए

उस की ड्यूटी है कि अगर कोई इधर की बात उधर करता है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो उस के विरुद्ध कार्यवाही करे। हमतो यह चाहते हैं कि हमारे जितने शासकीय कर्मचारी हैं—वे कर्तव्यपरायण हों, कर्त्तव्य-निष्ठ हों। हमें उन को इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए तथा देश में ऐसा वातावरण होना चाहिए कि जो भी सर्विस में हो या बाहर हों, वे देश-प्रेमी बनें, देश-भक्त बनें, जनता का जो भी काम उन्हें करना है, वह ईमानदारी से करें। यह भावना हमें देश में पैदा करनी होगी और ऐसा करने के लिये यदि हमें अपने कानूनों में कुछ तबदीली भी करनी पड़े तो हमें उस के लिये तैयार रहना चाहिये। आज हम एक नये युग में प्रवेश कर रहे हैं, इस लिए जो ऐसी परम्परायें हैं, ऐसे कानून हैं जिन को हम समाज के लिये अच्छा नहीं समझते हैं, उन्हें बदल डालना चाहिए।

आज आप देखेंगे—बहुत से विभागों में जो कैजुएल लेबर होती है—किसी ने 6 महीने काम किया है या एक वर्ष काम किया है, यदि वह रेगुलर बनने की कोशिश करता है या कोई दरख्वास्त देता है कि मैं इतने वर्षों से काम कर रहा हूं, मुझ को रेगुलर बना दिया जाय, तो हमारे अफसर फौरन उस से नाराज हो जाते हैं और उस को निकाल देते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण हैं—जहां उन को निकाल दिया गया है ताकि वह रेगुलर न हो सकें। इस लिये मैं आप से कहना चाहता हूं—किसी की जिन्दगी किसी की कृपा पर निर्भर नहीं रहनी चाहिए। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी यदि इस में थोड़ा-बहुत हेरफेर करना चाहते हैं तो वे जरूर करें, उस में मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन इस तरह से कहना कि जो बातें कही गई हैं वे सब सही हैं या हम उनको सही मानते हैं, भावना बहुत अच्छी है, लेकिन इस को पास नहीं करना चाहिए—यह ठीक बात नहीं है। यदि भावना ठीक है तो वह कार्य रूप में परिणित होनी चाहिए, जिस बात को हम अच्छा समझते हैं – उस को लागू किया जाना चाहिये। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं—यदि जनता पार्टी की सरकार अपने उद्देश्यों में मजबूत है, अपने कार्यकलापों में मजबूत है, सही काम करेगी, तो सारे देश की जनता और विपक्षी दल उस का साथ देंगे। हमारे देश का प्रजातन्त्र तब ही मजबूत रहेगा जब देश की जनता के लिये सही काम करेंगे इस देश में तानाशाही नहीं रहेगी। आप देखते हैं— बहुत सी जगहों पर चापलूसी करने वाले, जो बहुत होश्यार हैं, रिश्वत भी देते हैं—उन की नौकरी बनी रहती है, चाहे वे घर पर ही बैठे रहें, ड्यूटी पर आयें या न आयें और जो निष्पक्ष, ईमानदार हैं, उन के साथ अन्याय होता है। इसलिये मैं कहता हूं कि हम जिन बातों को अच्छा समझते हैं हमें उन को मानना चाहिये। चाहे शासकीय व्यक्ति हो या अशासकीय व्यक्ति हो—सब को एक तरह से काम करना होगा, लगन से काम करना होगा, सही काम करना होगा, किसी की कृपा पर किसी की जिन्दगी नहीं होनी चाहिये। इसलिये मैं इस विचार-धारा का समर्थन करता हूं।

*SHRI A. SUNNA SAHIB (Palghat): Mr. Chairman, Sir, though I am not in a position to welcome the Constitution Amendment Bill of my hon. friend Shri Bhagat Ram, in its entirety, I would like to commend the spirit behind this significant Bill.

Article 309 of the Constitution adumbrates that Acts of appropriate Legislature may regulate the recruitment, and conditions of service of persons appointed to public services and posts in connection with the affairs of the Union or of any State

*The original speech was delivered in Tamil.

[Shri A. Sunna Sahib]

It is recognised that such rules and regulations governing the Services will be in consonance with the statutes enacted by an elected Assembly. It also ensures that man is not infallible, in whatever position he is placed. The decision making process involves certain risks and without taking such risks we cannot ensure development in any sphere of human activities. But these mistakes should not incur the wrath of vengeance from the superior Officers. It should be tempered by natural justice. There should be built-in safeguards for protecting those who commit genuine mistakes in the process of implementation of decisions. If mistake are to be penalised without giving opportunities to those people for correcting themselves, then the governance of the country will be in jeopardy.

Articles 310 and 311 speak about the tenure of office of persons serving the Union or a State subject to the pleasure of the President or the Governor and also about the processes of dismissal, removal or reduction in rank of such persons. The pleasure of the President or the pleasure of the Governor does not mean that the President or the Governor takes direct interest or involvment in the process of implementation of service rules. It is only the superior Government Officers who take power in their hands to do such things. I do not say that offences should not be punished. But I would like to point out that unbridled penalties will prove banal to constitutional provisions of fairplay and natural justice. One should be made to realise that he has committed a mistake; but the punishment should not deter him from taking any decisions at all.

As has been pointed out by the Members who preceded me, there is a sea-change of difference between pre-Independence conditions and post-Independence conditions. We have incorporated in our Constitution certain portions of 1935 Government of India Act according to which the Service rules have been framed. In the Republican India, the circumstances demanded a different orientation. We have changed from a colonial atmosphere into a welfare atmostphere. The present constitutional provisions do require certain amendments in this regard.

Sometime back the chance for judicial review of the Service rules was supplanted by Administrative Tribunals comprising high Government officials. This was actually denial of natural justice to the Government servants, who like any other citizen of the country, are entitled to enjoy basic fundamental rights. We cannot have two sets of constitutional provisions for the people of the country. We must restore the opportunity of judicial review for the Government Services They should have the right to go to Court of laws and not chained to Administrative Tribunals.

I will refer to Article 311(2)(b) of the Constitution which states:

> Where an authority empowered to dismiss or remove a person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason, to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to hold such inquiry.

How can we have such a provision in the Constitution that without due process of inquiry a Government servant can be punished for an alleged offence which need not be recorded also? This contravenes all constitutional properties.

Now you see provision 311(2)(c) which reads:

> Where the President or the Governor, as the case may be is satisfied that in the interest of the security of the State it is not expedient to hold such inquiry.

Here the President and the Governor are dragged, as if the 'authority'

under 311(2)(b) is different from the highest authority of the land the President in respect of Union and the Governor in respect of the State. One contradicts the other. I am afraid that the constitutional sanctity becomes the victim of these anachronisms. There must be constitutional philosophy behind what we do in a democracy. I do not want to condemn everything of what Janata Government does. But I would like to be critical where the Janata Government fails to act within the framework of constitutional proprieties.

In a democracy it is not that the high administrators should not give orders to the subordinates. If we create that climate, then all the executive functions will come to a standstill. As the great political philosopher Laski has said, there should be that hyphen which joins and that buckle which fastens. There should be this bridge between the superiors and the subordinates in the Government. But it is essential to maintain a climate of trust rather than a climate of mutual bickerings and an atmosphere of vengeance.

I would conclude by saying that the Service conditions should be subject to acts of Legislatures and the areas of arbitrariness should be removed for ever in the sphere of State activities. We cannot take anyone of the Articles 309, 310 and 311 in isolation. If my friend Shri Bhagat Ram had brought a comprehentive amending bill, I would have unreservedly extended my support. Now, I extend my support to the spirit of his Bill and I hope that the Government would concede the need for doing something in this regard.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS AND IN THE MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI S. D. PATIL): Mr. Chairman, Sir, the Bill received mixed reception . . .

SHRI SOMNATH CHATTERJEE (Jadavpur): Majority supported it.

SHRI S. D PATIL: There was qualified support and also stiff opposition . . .

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Only one member opposed it.

SHRI S. D. PATIL: During the last 29 years, there was no attempt for scrapping or deleting article 310 as well as article 311 (2)(c) except a Private Member's Bill in 1977 by Shri Chitta Basu who moved the Bill for scrapping article 311 (2)(c) only. But the Bill did not come up for a discussion.

Now, the hon. Member, Mr. Bhagat Ram, an erstwhile teacher who had an important role to discipline his pupils and also to hold out values which can inculcate a spirit of loyalty to the nation and patriotism has now chosen to move this Bill for the deletion of article 310. His opposition is on two or three grounds. Firstly, he says that it is a relic or a vestige of the Victorian era, that it hits the legitimate growth of trade union activities and that persons who are in the Government services are affected by it. This Art. 310 should not be read in isolation, because these two Articles 310 and 311 should be read together. A brilliant Advocate, Mr. Somnath Chatterjee is always very convincing but in the advocacy of this particular Bill he has not given convincing reasons as to why Art. 310 should not be read with Art. 311. Of course, I belong to that profession and I know that whenever it is inconvenient to quote or give a correct idea, Lawyers do not reveal the full implications, and he has chosen to do so.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Let us hear the real implications from the Minister: let us see how the Minister has understood this. He has got a brief. His brief is prepared by the bureaucrats. I am holding

[Shri Somnath Chatterjee]

the brief of the people and not of those who are against the people; that is the difference.

SHRI S. D. PATIL: The question is, ours is a democracy, which is criticised for its rule-bound administration. There is not a single case of a Government servant who is not controlled by Rules, whether he holds a temporary service or a permanent service, and there are so many steps before he is visited with punishments which are styled as major punishments. Here we are concerned with services under the State and the Union and there, too, only as far as the three major penalties are concerned—dismissal, removal or reduction in rank. As far as other minor penalties or even other penalties are concerned, we are not concerned with them here.

So, the opposition is to the doctrine that services are held, as far as the Union is concerned, during the pleasure of the President and, so far as the States are concerned, during the pleasure of the Governor. This particular doctrine is objected to on the ground that the powers exercised are not directly exercised by the President or Governor but by their representatives who are in the Government and that too, they say, it is done at a junior level.

I will give you the procedure here, but the procedure is so eaborate . . .

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: May I seek a clarification? Nobody is disputing that Arts. 310 and 311 have to be read together but will the Hon. Minister tell us whether the Defence Personnel or civilians in Defence services are protected by Art. 311? Let us know this.

MR. CHAIRMAN: Let him complete.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: What is the good of elaborating the procedure under Art. 311? Everybody knows it. Whether civilians in Defence Services like Clerks, Motor-car Drivers . . .

MR. CHAIRMAN: Let him finish and if necessary you can ask questions later.

SHRI S. D. PATIL: Certain Services, particularly Military Services, must have a different code of conduct because it is a very sensitive area where people have to work under a certain discipline. Even these civilians in Defence Services have a certain duty to perform because their services are concerned with military operations, even though they may be styled as civilians.

Let us look to the procedure—because it was made out that a number of people suffered during the Emergency. Nobody pointed out whether people had suffered, and to a very large extent, before the Emergency.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Yes, I have said that. I mentioned 1965 and 1971. The Minister has not got the particulars. I have said that.

SHRI S. D. PATIL: As far as statistics are concerned, there were as many as 71 cases during the Emergency out of which, except 3, 63 people were reinstated.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Why? They were reinstated because the dismissals were wrongful. They took recourse to the Draconian provision under the garb of the security of the State and 63 people were illegally dismissed. That shows the inappropriateness and Draconianness of the provision.

I would request the Hon. Minister to appreciate the feelings of the Members. If they go on annoying the

Government servants, I don't know what will happen.

SHRI S. D. PATIL: Instructions laying down a detailed procedure for dealing with cases under the proviso (c) to Article 311(2) of the Constitution were first issued in 1968 and subsequently amplified in 1972. Care has been taken to eliminate any chance of abuse of power in taking action against employees under the aforesaid provision. The procedure laid down by the 1972 instructions prescribes that the Secretary of the administrative Ministry/Department concerned—so, it is not at the junior level—should examine the case and if he recommends that action should be taken against the government employee under the proviso (c) to article 311(2), the case is referred to a Committee of Advisers headed by the Home Secretary for consideration. Kindly listen to me and then you may point out if the procedure is faulty or it is a procedure which is adopted at the junior level, by not very responsible people, by persons who are actuated by certain prejudices or motives or certain vendetta. You will find that the procedure is not so. The case is referred to a Committee of Advisers headed by the Home Secretary for consideration. The Committee goes into the details of the activities of the employees concerned and then recommends whether the case is fit enough to warrant dismissal or removal of the government employee by invoking the aforesaid provision. If the recommendation is in favour of taking action against the employee, the case is submitted to the Minister in the Department of Personnel and Administrative Reforms for his approval. If he also approves the course of action, the case is further processed by the Ministry/Department concerned which issues the orders only after obtaining the approval of the Minister-in-charge. Thus, there are sufficient safeguards for any person who comes under the provision of article 311(2)(c), and the procedure is quite elaborate...

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: What is Government's definition of 'security of State'?

SHRI S. D. PATIL: I will come to that also.

As I said, the procedure which has been prescribed starts from the Secretary, then it goes to the Committee, then to the Minister of State, then to the Minister. There is thus sufficient responsibility which has been prescribed. Before a man is condemned, he is given all possible opportunity...

PROF. P. G. MAVALANKAR: He has read out the whole procedure. So far so good. But he has not replied to the main point that, in the whole procedure, the people involved in going through the cases are all Central Government servants and Ministers; it has not provided for independent people. Also how do you define 'security of State'?

SHRI S. D. PATIL: If a knowledgeable and brilliant professor like Prof. Mavalankar considers Minister and Ministers-in-charge also along with government servants.... (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN: Prof. Mavalankar, let the Minister give his complete reply first. You may make a note of all the points and raise them after he has finished.

PROF. P. G. MAVALANKAR: Allright, Sir. Let him make his complete speech.

SHRI S. D. PATIL: Even if this procedure is adopted, ultimately, the dismissed government servant or the person who is removed has a right to present a memorial to the President. He can also go to the High Court or the Supreme Court in a writ petition. So, the decision is also justiciable. Even though it is worded...

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Writ petition for dismissal under article 311(2)(c)!

17.00 hrs.

SHRI S. D. PATIL: The person is not without a remedy. He has got all the remedies.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Supreme Court writ petition is under Art. 32. Does Art. 311(2)(c) deal with Art. 32? I do not know what the hon. Minister says? After all this is Parliament of India and Government employees are involved—and this is the reply which is being given! We would like to know what is the Government's stand?

SHRI S. D. PATIL: Government's stand—I am making quite clear.

If we come to the number of cases during the two years of 1977 and 1978 and upto this date, we have not got a single case in which this particular authority was utilised. So it only indicates that there is not sufficient justification for the deletion of this clause. After all, the Government must have power to remove a person who is found undesirable. Where is his liberty curtailed? It is only under Art 311(2)(c). There also, where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied that in the interests of the security of the State... Here also this particular provision is not utilised in a casual manner but all possible and detailed inquiries are being made before we utilise this particular procedure.

Now, the term 'security of the State' is quite obvious. I do not think it needs to be defined...

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: It needs. At least Judges have not yet been able to define.

SHRI S. D. PATIL: Everything cannot be defined. There are certain connotations and well-accepted meaning. Security of a person, security of the State—these things cannot be defined...

PROF. P. G. MAVALANKAR: It is because he is sitting there.

SHRI S. D. PATIL: There is no difference whether a person is there or here. The question is: where the founding fathers have, in their wisdom, chosen to allow these two Articles to remain on the statute book and on the Constitution and there is no demand during the last 27 years and even during the emergency nobody raised it and even earlier when it started, even a brilliant Professor like Prof. Mavalankar who now subscribes to the substance and spirit of this particular demand...

PROF. P. G. MAVALANKAR: I did.

SHRI S. D. PATIL: With all his eloquence he tries to show but he was not also very convincing on this point—why the doctrine of pleasure should be dispensed with. Should the government function without any authority? Now, take the security of the State. The question is of espionage. Even here, I say only 8 persons were detained during the emergency. Out of 71, 63 have already been reinstated...

PROF. P. G. MAVALANKAR: Why?

SHRI S. D. PATIL: Because the particular procedure might not have been followed or sufficient evidence might not have been there... (*Interruptions*).

SHRI P. K. KODIYAN: What were the reasons?

SHRI S. D. PATIL: I am not having all the details here. During the emergency they were reinstated... (*Interruptions*). It is not under the cover. The question is no legitimate activity of any trade union or any government servant when he wants to have some association is thereby curtailed. The question is: whether we can allow

our servants to go on a rampage and indulge in activities which will amount to sabotage or which will be detrimental to the security of the State. So the inquiry is dispensed with only in rare cases. There also, the provision lays down that where the President or the Governor, as the case may be, is satisfied—so there is the subjective satisfaction—that in the interests of the security of the State it is not expedient to hold such an inquiry, because it is very inconvenient. Suppose a person who indulges in espionage activities or activities which amount to sabotage—it is difficult. Are there any cases in government servants who really pass on information and act as agents? We have a number of instances where we keep a watch because in the IB Department—I cannot disclose everything. Persons who cannot be suspected, persons who are engineers, persons who are scientists and persons who are holding a number of responsible posts—they are under watch, for in regard to certain activities which amount to espionage or sabotage. Such persons are to be watched and if you try to gather the information and give the opportunity of an open inquiry which is usually available to other services, it will frustrate the very object of inquiry.

And it will be dangerous. A number of documents can be suppressed or destroyed.

Clause (3) says:

"(3) If in respect of any such person as aforesaid, a question may be, is satisfied—so there is the arises whether it is reasonably practicable to hold such inquiry as is referred to in clause (2), the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person or to reduce him in rank shall be final."

Here also it is mentioned that unless it is not reasonably practicable to hold an inquiry, the inquiry will not be dispensed with.

So, Sir, the two Articles are quite inter-dependent and where there is not sufficient data to come to the conclusion that this power was misused either in the past, during the emergency or even after that, I do not think there is sufficient justification for doing so. Therefore, even though there is a mixed reaction yet on behalf of the government I am opposing the deletion of these two Clauses.

Now, Sir, Mr. Chatterjee is outside the pale of the Ministry. If he were occupying a place in the Cabinet of Shri Jyoti Basu he would have realised the responsibilities of the state. (*Interruptions*) I think his support to the Bill is more from the party point of view or some sort of a support to a friend.

AN HON'BLE MEMBER: What about Prof. Mavalankar?

SHRI S. D. PATIL: Mr. Mavalankar is a very intelligent persons. What he has done is tight rope walking.

Now, Sir, Mr. Kamble mentions about 'temporary' and 'permanent'. This is a complicated and vexed question. As to what rules should govern temporary staff and what rules should govern permanent staff these have been framed after some practical considerations. Supposing a particular rule acts against the interests of the person concerned then he can make a demand for change of the rules but we cannot agree to such a drastic bill which seeks to delete Article 310. It seeks to destroy the very foundation of the government. (*Interruptions*)

SHRI B. C. KAMBLE: Article 311 does not make any difference between 'temporary' and 'permanent'.

SHRI S. D. PATIL: I do not want to turn the discussion here as in the court of law. Every lawyer has his own way of presentation. Government is incharge of the whole nation. So we have to see that the interest of

[Shri S. D. Patil]

the State and the security of the State is taken care of more than anything else. Governments may come and go. But you know, the 'security of the State' must remain. That is the very fundamental principle which has been accepted by us in our constitution. The founding-fathers of the Constitution had no hesitation in this. I had read through all the comments on Article 310 and 311. I have not found a single comment in which the views which are expressed by Mr. Somnath Chatterjee and his friends found a place. Some friends are being led away more by certain circumstances which prevail in the trade union, as far as temporary services are concerned, as far as discharges and removals are concerned. They are more exercised over those things. That is a different matter. We have to separate these two things and we must come to the predominant or dominant consideration. That is, the security of the State. Here only this Article 311(2)(c) operates.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: You are advocating a bad cause

SHRI S. D. PATIL: May be; I don't want any bouquet. I do not think that the various speakers have made out sufficient justification for their stand. Ours is a democracy where we have not got a committed bureaucracy. We have no spate of offices which we can offer to our partymen and so on. Here in this country even during emergency, some people might have been favoured but not all of them, because, we have no right in our Constitution to choose people from outside, except in the case of some Private Secretaries and some personal staff, which are given to the Ministers. Except that limited thing, we have no authority to change the Secretary or the permanent staff. So the staff is there. It is our permanent set up which governs the country through well-regulated rules. Those rules will not come in the way of successful working of trade union activities. These activities are well-protected under the various labour laws. And I think we have gone much further than what the situation in the country warranted. We have to create discipline, loyalty and patriotism in all our ranks. Those who are serving under the Government also owe a duty to this country; they should not indulge in any subversive activities.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Start with your own party first.

SHRI S. D. PATIL: My party is quite safe. We are hand-in-glove; our friendship is mutual, based upon trust; so with my party; don't worry about my party. It is strong and it can take care of itself.

Shrimati Parvathi Krishnan said one thing. She is not here. She said that the lady who had advocated 'garibi hatao' was herself 'hataoed'. She was 'hataoed' by the people because of her acts of commission and omission. Here we are quite safe that during the last 24 months not a single case has come to our notice wherein we have used this Article. So, we are quite clear in our minds and in our actions. I have given some instances during the emergency. There were 71 cases; necessary things by way of restoration have been done in 63 cases, 8 cases are there. They are concerning the activities of sabotage, espionage etc. Beyond that I don't think there are any cases where we can say that they are against the legitimate rights of the Government servants under the State or under the Centre's control. I think I have dealt with many of the points raised in this House and I will request Mr. Bhagat Ram to withdraw his Bill. I must compliment him for one thing. He is a very very diligent Member. He always writes at least half-a-dozen letters to me in a month. I would only tell him that he deserves sufficient support for his point of view, though it may not be a support for

the amendment to the Constitution. For that there is a certain procedure which requires to be fulfilled for passing. But he has really given a good thought in bringing this Bill forward. But I would like to point out that while pointing out certain problems during the debate that this particular Article requires some amendment, how that amendment should be really made has not been suggested by anybody including Prof. Mavalankar and the great advocate Mr. Somnath Chatterjee. What is the substitute to this, how do you want to tackle the situation? This country should be run safely without endangering democracy. It should not be done in such a way that every man has got fundamental rights and he should not be allowed to do anything so that the country may be put to trouble because of his activities. It should not spoil the security of the State. Therefore, I think there is not adequate and sufficient justification for the deletion of the clause suggested by him. I would request Mr. Bhagat Ram to withdraw his Bill.

PROF. P. G. MAVALANKAR: I admire my esteemed friend for the manner in which he has tried to put the case. He has, however, missed the very burden of our argument. What we expected at least I expected —of the Janata Government is, this assurance, that on the basis of the experience over the past so many years, and particularly during the Emergency, if this kind of blanket provision of the security of the State can be misused by the Governments and they can act as arbitrary agents to remove people and deny them natural justice, would not the Janata Government at least be receptive enough to look into this matter instead of out-right saying 'No, we are right'? If not, what is the difference between you and Mrs. Indira Gandhi's Government, I want to ask this. You take this attitude after coming to power. When they were not in power the attitude was different, but having come to power they should not take a different attitude. At least they should be humble and receptive to the possibility of abuse of arbitrary power which is inherent in Article 311. Finally, he is asking: what is the alternative suggestion? Are we not going to sit together and discuss this to find what could we do? This is my point.

SHRI S. D. PATIL: It is not an assurance that there has not been a single case during these months. There is not a single case under this Article.

PROF. P. G. MAVALANKAR: The point is that you have reinstituted the Emergency cases. Why? So, there is a case for removing part of that provision under article 311.

SHRI S. D. PATIL: Even during the Emergency, only 8 cases were found. That is the main point. Only 8 cases were found. The rest are reinstated.

MR. CHAIRMAN: I think the point made by Prof. Mavalankar is that it may be or may not be but will you be in favour of having such a blanket power with the Government ever? This is what he wants to know.

SHRI S. D. PATIL: In the first place, it is not a blanket power or blank power. It is not an arbitrary power. It is a power which can be reasonably used under particular circumstances with an elaborate process of enquiry. It is not as if we are very summary and very casual in the enquiry. It is an elaborate enquiry starting from the Secretary, then the Committee, then the Minister of State, then the Minister Incharge. So all these precautions are taken in all these processes. We need not feel that there is not enough and sufficient guarantee.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: Sir, the hon. Minister has said that there is an elaborate procedure for getting rid of an employee under Article 311(2)(c) because there is an elaborate enquiry starting from the Secretary, then here is some Advisory Committee. Then comes the Minister

[Shri Somnath Chatterjee]

of State. The Deputy Minister will perhaps also come in if there is one like Mr. Mohsin, because he had also to do something. Then the Cabinet Minister and Prime Minister also; I do not know.

This Government has realised that out of 71 cases, 63 cases had been illegally dealt with. Therefore, 63 employees who did not deserve to be dismissed under Article 311(2)(c) were dismissed even after following the elaborate procedure of in-built checks. Is it or is it not a lesson that even without declaring emergency, that arbitrary power is inbuilt in the Constitution? This is an ordinary provision, not an emergency provision. Therefore, emergency or no emergency, this provision always remains in the Constitution and it can be taken recourse to. There has been such a gross abuse of authority in 63 cases out of 71 cases. Not only during the emergency, but even prior to that, there have been umpteen cases where they have taken recourse to this. Has a case not been made out for a thorough examination of this? The Minister is not even prepared to look into this matter and he is taking up the attitude that the Government can do no wrong. He is behaving, His Majesty Patil, is behaving that the 'King can do no wrong'. How can there be that in 63 cases out of 71 cases this was taken recourse to illegally, if there was an elaborate process to prevent the arbitrary abuse of authority?

Both espionage and sabotage—the two things that the hon. Minister has mentioned—are very serious offences under the Indian Penal Code, Official Secrets Act etc. The Government servants who are even suspected to be guilty of these offences can be immediately suspended and tried. Once they are tried and found guilty by a criminal court of law, under Article 311(2)(c), they can be dismissed without an enquiry. Kindly look at Article 311 Therefore, a person guilty of espionage and sabotage can be made to lose his job under Article 311 if he is found guilty by a court of law. Why not that person be given a chance to protect himself in a court of law? He may be dismissed under Article 311(2)(c) without any enquiry on the plea of security of the State and in a criminal case he may win. What is his fate? What is this arrogant attitude of the hon. Minister and the Department?

The hon. Minister spoke of mixed reception. What is the mixed reception? Some hon. Members have supsupported the emergency have supported it and those who did not support the emergency have not supported it. We are only appealing to the hon. Minister. We know we cannot get this Bill passed. We are only appealing to the hon. Minister not to take up the attitude that you can never be wrong and that people have no apprehension about it. I can tell the hon. Minister that the Government employees will not accept it; they will go on agitating. If they want to have a confrontation with their own employees, it is for them. They should take an attitude which would help everybody.

SHRI B. C. KAMBLE: I would like the hon. Minister to give an assurance that at least he will get this examined whether Rule 5 is consistent with Article 311. Article 311 does not make any distinction between temporary and permanent employees. Under the garb of Rule 5, so many temporary employees have been removed without any kind of enquiry.

SHRI S. D. PATIL: I cannot give the assurance, but I will examine this question.

As regards the point made out by Shri Somnath Chatterjee, sabotage or subversive activities is not an offence uptil now. We are just thinking to bring amendments in the Indian Penal Code for the purpose. Espionage is there, but not sabotage or subversive activities. I do not deny the validity of his point of view that

during emergency this was misused and that is why we had reviewed the cases. And 63 cases were reviewed. I do not say that it is not subject to misuse. I did not say that. But what I have pointed cut is that even during the Emergency, the number was only 71 not a big enough number; but the number was big enough when it was reviewed and found that 63 persons were to be re-instated; and that really gives some scope for reconsideration. That is, any such Government is likely to misuse it under some pretext of Emergency or something else; and so, it requires some reconsideration.

MR. CHAIRMAN: If I follow it, his point is that out of 71 cases, 60 cases were to be reviewed. So, is it not an abuse of the process?

SHRI S. D. PATIL: I do grant that during Emergency, it was abused. (*Interruptions*) I am not too much on statistics. I am realizing that when a Government is really tempted to use this power, that power will be misused—by certain persons who are in power. We will very carefully examine. That is why, when you follow the elaborate procedure, there is no likelihood of misuse. All the same, I realize the intensity of feeling behind this Bill, and of feelings of those who supported the Bill. I do not say that there is no validity. There is some validity.

SHRI SOMNATH CHATTERJEE: It requires so many interruptions to get a little modification. Mr. Chairman, Sir, we are thankful to you for having come to our help

श्री भगत राम (फिल्लौर) : सभापति महोदय, मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे बिल, जो कि धारा 310 और 311 को निरसित करने के लिये पेश किया था, पर बहुत से माननीय सदस्यों ने डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया। मैं उन सब का आभारी हूं। खासकर यह देखकर मुझे और भी खुशी होती है कि लगभग 20 सदस्य इस बिल पर बोले हैं और सभी ने इस बिल की भावना को सपोर्ट किया है। 3, 4 सदस्य इस बिल के विरोध में भी बोले लेकिन वह भी पूरी तरह से इस बिल को अपोज नहीं कर सके, उन्होंने भी अपनी स्पीचेज में आधे से ज्यादा इसको सपोर्ट ही किया। आखिर में क्योंकि पार्टी का डिसिप्लिन है, तो उसको देखकर उन्होंने इसे अपोज किया, लेकिन मैं जनता पार्टी के उन माननीय सदस्यों को बधाई देता हूं, जिन्होंने पार्टी के डिसिप्लिन को मान कर वह वोट तो इसके विरुद्ध देंगे, लेकिन उन्होंने इस बिल को होल-हार्टेडली सपोर्ट किया है। उनको सरकार की जो पालिसी है, जैसा कि मिनिस्टर साहब ने एक्सप्लेन किया है, उसकी भी उन्होंने परवाह नहीं की है, उनको फिर मैं बधाई देना चाहता हूं।

मुझे इस बात की हैरानी है कि मिनिस्टर साहब ने जो गवर्नमेंट की तरफ से इसे एक्सप्लेन किया है, उन्होंने इतने सदस्यों की भावनाओं का तिरस्कार करते हुए इस बिल का विरोध किया है। उन्होंने ऐसे आर्ग्यूमेंट इसमें दिये हैं जो किसी को भी एक्सपेक्टेबल नहीं हैं, यही कारण है कि हर तरफ से मिनिस्टर साहब की स्पीच में इंटरप्शन हुआ और उनकी पार्टी के लोग भी उनको उसमें बचाने के लिये नहीं आये।

मुझे यह भी हैरानी है कि जो गवर्नमेंट डिक्टेटरशिप को फाइट कर के इस गद्दी पर बैठी है, उसके रिप्रेजेंन्टेटिव इस तरह की बातें करते हैं, जिससे लगता है कि यहां पर इन्दिरा गांधी सरकार की पराजित नीतियों पर चला जा रहा है। यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे आर्ग्यू करते हैं जैसे प्राइवेट

[श्री भगत राम]

एम्पलायर के लोग आर्ग्यू करते हैं। इस बात से बड़ी हैरानी होती है।

जिन्होंने इस बिल को अपोज किया है, उन्होंने भी यह डाउट जाहिर किया है कि अगर इस आर्टिकल को डिलीट किया जाता है तो जो लोग करप्ट हैं, उनको प्रोटैक्शन मिलेगा। आप पिछली हिस्ट्री देखिये कि कितने करप्ट लोगों के खिलाफ इन आर्टिकलज का इस्तेमाल किया गया है। आपको बहुत कम ऐसे आदमी मिलेंगे, जिनके खिलाफ करप्ट होने की वजह से इन का इस्तेमाल किया गया हो। इनका इस्तेमाल या तो ट्रेड यूनियन के लीडर्ज के खिलाफ किया गया है, या ऐसे ईमानदार एम्प्लाई के खिलाफ किया गया है, जो अपने बासिज ब्यूरोक्रेट्स, की करप्शन को नंगा करना चाहते थे। मिनिस्टर साहब ने जो कुछ बताया है, उससे भी यह बात साबित हो जाती है।

कांस्टीट्यूशन में बहुत से प्राविजन्ज हैं, सर्विस कन्डक्ट रूल्ज है, जिनके जरिए करप्ट लोगों से डील किया जा सकता है। यह कहना ठीक नहीं है कि इन आर्टिकल्ज को रख कर ही उनसे डील किया जा सकता है। मिनिस्टर साहब और इस बिल को अपोज करने वाले सदस्यों ने बताया है कि सिक्युरिटी आफ स्टेट के लिए ये आर्टिकल बहुत जरूरी हैं। प्रोफेसर मावलंकर ने सवाल उठाया है कि सिक्युरिटी आफ स्टेट के बारे में कौन डिसाइड करेगा। चूंकि उन्होंने इस बात को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा नहीं जाना चाहता हूं।

शाह कमीशन ने, जिसको इस सरकार ने लोगों की भावनाओं को देख कर बिठाया था सिक्युरिटी आफ स्टेट की बात को एक्सपोज करके रख दिया है। उसने इसको एक धोखा बताया है और कहा है कि इमर्जेन्सी लगने से पहले सिक्युरिटी आफ स्टेट को कोई खतरा नहीं था। जो लोग आज सरकार में बैठे हैं इमर्जेन्सी के दौरान सिक्युरिटी आफ स्टेट के नाम पर उन पर कितने अत्याचार किये गये और कितनी देर तक जेल में रखा गया। हमारी पार्टी के लोगों, और दूसरे ईमानदार लोगों को भी भले ही वे कांग्रेस में क्यों न रहे हों, जेलों में रखा गया और उन पर कई अत्याचार किए गए—और यह सब कुछ सिक्युरिटी आफ स्टेट के नाम पर किया गया। मिनिस्टर साहब एक डेमोक्रेटिक कही जाती गवर्नमेन्ट के नुमाइंदे हैं। अगर वह ऐसे आर्ग्युमैन्टस दें, तो वह बड़ी हैरानी की बात है। इस हालत में कैसे यकीन किया जा सकता है कि यह गवर्नमैन्ट इस आर्टिकल को मिसयूज नहीं करेगी ?

जासूसी वगैरह के सिलसिले में किसी एम्पलाई को जल्दी रीमूव नहीं करने की जरूरत पड़ सकती है, या ऐसी कुछ जरूरतें हो सकती हैं। इसके लिए बहुत से प्राविजन्स हैं। ऐसे एम्पलाई को ससपैन्ड किया जा सकता है, उसको एरेस्ट किया जा सकता है। केस चला कर उसको सख्त से सख्त सजा दी जा सकती है। अगर सरकार इस आर्टिकल पर डिपैन्ड करती है, तो मैं समझता हूं कि वह लोगों, और सेंट्रल गवर्नमैन्ट तथा स्टेट गवर्नमैन्ट के एम्पलाईज की भावनाओं का तिरस्कार करती है और अपने ही कर्मचारियों पर यकीन नहीं रखती। सरकारी पक्ष की तरफ से सिक्यूरिटी आफ स्टेट की जो दलील दी गई है, उसमें कोई वेट नहीं है। माननीय सदस्य, प्रो० मावलंकर और दूसरे सदस्यों ने उसकी हवा निकाल दी है। अगर फिर भी गवर्नमेंट इस पर जिद करती है, तो यह बात बिल्कुल ठीक नहीं है। कुछ माननीय सदस्यों की ओर से और सरकार की ओर से भी यह बात कही गई है

कि जनता पार्टी जब से पावर में आई है तब से उस ने किसी भी एम्पलाई पर इसको यूटिलाइज नहीं किया है और यहां तक कि जनता पार्टी ने 71 में से 63 एम्पलाईज जो थे जिन पर इमर्जेन्सी में आर्टिकल का इस्तेमाल किया गया था उनको फिर री-इंस्टेट कर दिया है। ठीक है जनता पार्टी की जो यह भावना है और जो उन्होंने इस को यूटिलाइज नहीं किया है, इसके लिये मैं उन को बधाई देता हूं, उन्होंने अच्छी बात की है। लेकिन इन्होंने यह एश्योरेंस नहीं दी कि हम किसी एम्पलाई पर इसको यूटिलाइज नहीं करेंगे। इन्होंने यही बताया कि हमारे दो साल के राज के दौरान इसका मिस-यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इस देश में सदा के लिए गद्दी पर रहना चाहते हैं? कैसे हम लोग इस को मानें। अगर आप की यह भावना है तो कैसे यह माना जा सकता है कि यह गवर्नमेंट सदा गद्दी पर रहेगी और कभी इस को मिस-यूटिलाइज नहीं करेगी। मिनिस्टर साहब यह खुद मानेंगे कि जनता पार्टी के अन्दरूनी मामले जो हैं उस में जनता पार्टी वालों को भी यह यकीन नहीं है कि यह पार्टी बनी रहेगी या नहीं बनी रहेगी और यह पांच साल पूरे करेगी भी या नहीं। ऐसी हालत में ऐसी बातें कहना मैं समझता हूं कि अच्छा नहीं है और सचाई से आंखें मूंदना है।

मिनिस्टर साहब ने तो खुद यह माना है कि 71 में से 63 को इन्होंने री-इंस्टेट किया है। इसका साफ मतलब है कि जो ये मेजारिटी आफ एम्पलाईज थे उन पर इस आर्टिकल का गलत इस्तेमाल किया गया और इस लिए सरकार को उनके केसेज को रिव्यू कर के फिर उन्हें री-इन्स्टेट करना पड़ा। मिनिस्टर साहब ने यह भी कहा है कि इस के सेफगार्ड्स पहले से कांस्टीच्यूशन में हैं और यह भी है कि सेक्रेटरी लेवेल की कमेटी होती है, उसके पास ये केसेज जाते हैं और वहां इसे देखा जा सकता है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि जिन 63 केसेज को आपने री-इंस्टेट किया है इनके केसेज भी सेक्रेटरी लेवेल की कमेटी के पास गए होंगे। अगर वह कमेटी इन के साथ इंसाफ नहीं कर सकी तो क्या गारंटी है कि आगे वह कमेटी उनके साथ इंसाफ कर सकेगी?

यह भी कहा गया है कि जनता पार्टी रुल आफ ला में विश्वास करती है। यह अच्छी बात है। हम इनको उसके लिए बधाई देते हैं और हमारी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आप रुल आफ ला में विश्वास रखें, देश का इसी में भला है। लेकिन अगर यह इन को पक्का विश्वास है तो मैं समझता हूं कि इस बिल को अपोज करने का सरकार का कोई इरादा नहीं होना चाहिए, इन को इसे अपोज नहीं करना चाहिए। क्योंकि जिन आर्टिकल्स के डिलीशन की बात मैंने कही है वह तो रुल आफ ला नहीं है, वह तो रुल आफ जंगल है। अगर वह रूल आफ ला में विश्वास करते हैं तो इन को तो इस बिल को अपोज ही नहीं करना चाहिए बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि मुझे भी इस बिल को लाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी, 45वां अमेंडमेंट जब उन्होंने किया था तो उसी के साथ उन को इसे भी डिलीट करवा लेना चाहिए था।

कुछ सदस्यों ने यह भी कहा है कि आर्टिकल 310 को डिलीट करने की जरूरत नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि मुख्य रूप से दो मकसदों को सामने रख कर मैंने इस को रिमूव करने के लिए कहा है। एक तो यह कि इस में जो प्लेजर डाक्ट्रिन है, जैसा कि मैंने अपनी पहली स्पीच में बताया था, यह विक्टोरियन एरा का है और यह हमारे देश पर और हमारे कांस्टीच्यूशन पर एक कलंक और धब्बा है। माननीय श्री ने और दूसरे माननीय सदस्यों ने इस को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। इसलिए यह

[श्री भगत राम]

बिलकुल इस में नहीं रहना चाहिए। 311 में जो प्रावधान है कि :

"No person who is a member of a civil service of the Union or an all—India service or a civil service of a State or holds a civil post...."

इसमें डिफेंस का जिक्र नहीं है। ठीक है, डिफेंस में अगर कोई जासूसी करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन डिफेंस में बहुत से सिविलियन्स भी काम करते हैं, उन पर भी यही चीज लागू होती है। हजारों ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं। इसलिए मैंने इस आर्टिकल को भी रिमूव करने का प्रस्ताव किया है

इसके अलावा जब हमारे मिनिस्टर साहब बोल रहे थे तब उन्होंने हमारे कामरेड सोमनाथ चटर्जी साहब से कहा कि अगर आप श्री ज्योति बसु की जगह पर होते तब आपको पता चलता कि कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट कैसे किया जाता है। मैं मिनिस्टर साहब की जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि जहां तक वेस्ट बंगाल में हमारी पार्टी की गवर्नमेंट का सम्बन्ध है उसने इमर्जेन्सी में निकाले गए 15 स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाईज को ही रि-इंस्टेट नहीं किया बल्कि इमर्जेन्सी से पहले भी श्री सिद्धार्थ शंकर राय के जमाने में जो 13 स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाईज निकाले गये थे उनको भी री-इंस्टेट किया है। साथ ही मैं जानना चाहता हूं कि आर्डनेन्स फैक्टरी के 32 एम्पलाईज श्री सिद्धार्थ शंकर राय के जमाने में 1972 में जो निकाले गये थे उनको क्या आप री-इंस्टेट करने के लिए तैयार हैं ? इसी तरह से इस आर्टिकल के मातहत सैकड़ों एम्पलाईज को जो ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में पहले निकाले गए उनको क्या इस गवर्नमेंट ने री-इंस्टेट किया है ? चूंकि मिनिस्टर साहब ने कामरेड सोमनाथ चटर्जी को चैलेंज किया था इसलिए उनको बताना चाहता हूं कि आल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाईज की जो फेडरेशन है उसको मान्यता देने वाली पहली वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ही है अलावा त्रिपुरा और केरल गवर्नमेंट के। स्टेट गवर्नमेंट एम्पलाईज की जो फेडरेशन है वह सेन्टर से भी तथा अन्य स्टेट गवर्नमेन्ट्स से भी मांग कर रहे हैं कि उन्हें मान्यता दी जाये तो क्या इस माम ले में आप श्री ज्योति बसु को फालो करेंगे ? क्या जिस प्रकार से वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने उस फेडरेशन को मान्यता दी है, आप भी उसको मान्यता देंगे ?

अन्त में मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस बहस में पार्टिसिपेट किया है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अपील करूंगा कि वे बिना किसी पार्टी का लिहाज किए हुए इस बिल को सपोर्ट करें, इसके पक्ष में अपना वोट दें ताकि तीस लाख सेन्ट्रल एम्पलाईज और चालीस लाख स्टेट गवर्नमेन्ट्स एम्पलाईज जो कि लगातार बहुत देर से इस आर्टिकल को निकालने की मांग कर रहे हैं, उनकी भावनाओं को अमली रूप दिया जा सके। साथ ही मैं गवर्नमेंट से भी अपील करना चाहता हूं कि आप डेमोक्रेट हैं, आप डिक्टेटरशिप का अन्त करके इस कुर्सी पर बैठे हैं, आप इस अनडेमोक्रेटिक आर्टिकल को डिलीट करने में मदद करें। इस सदन को यूनानिमसली इस बिल को पास करना चाहिए।

SHRI S. D. PATIL: I have already requested him to withdraw the Bill. I have given the assurance that the Government will be careful to see that the article will not be misused in any way.

MR. CHAIRMAN: Are you withdrawing the Bill?

SHRI BHAGAT RAM: I am not withdrawing the Bill.

MR. CHAIRMAN: This is a Constitution Amendment Bill. So, there will have to be division on this. In that case, lobbies will have to be cleared. Now, let the lobbies be cleared. The lobbies have been cleared. This being a Constitution Amendment Bill I will straightaway put it for division. The question is....

SHRI HARI VISHNU KAMATH: One of the requirements for a Constitution Amendment Bill is half the total membership of the House. That is not present here.

MR. CHAIRMAN: I have to call for division. The question is:

"That the Bill further to amend the Constitution of India be taken into consideration."

The Lok Sabha divided:

Division No. 13] [17.52 hrs.

AYES

Austin, Dr. Henry
Banatwalla, Shri G. M.
Bhagat Ram, Shri
Bhakta, Shri Manoranjan
Burande. Shri Gangadhar Appa
Chatterjee, Shri Somnath
*Chaturvedi, Shri Shambhu Nath
Chikkalinglahi, Shri K.
Das, Shri R. P.
*Dhara, Shri Sushil Kumar
Gopal, Shri K.
Halder, Shri Krishna Chandra
Heren Bhumij, Shri
Kisku, Shri Jadunath
Kodiyan, Shri P. K.
Lahanu Sidavakom, Shri
Mavalankar, Prof. P. G.
Modak, Shri Bijoy
Roy, Shri Saugata
Saha, Shri A. K.
Saha, Shri Gadadhar
Sen, Shri Robin
Tirkey, Shri Pius

NOES

Arif Baig, Shri
Balak Ram, Shri
Balbir Singh, Chowdhury
Barakataki, Shrimati Renuka Devi
Borole, Shri Yashwant
Chunder, Dr. Pratap Chandra
Desai, Shri Morarji
Deshmukh, Shri Ram Prasad
Ganga Bhakt Singh, Shri
Joshi, Dr. Murli Manohar
Mahala, Shri K. L.
Mangal Deo, Shri
Mishra, Shri Shyamnandan
Nathwani, Shri Narendra P.
Nayak, Shri Laxmi Narain
Paraste, Shri Dalpat Singh
Patidar, Shri Rameshwar
Patil, Shri S. D.
Pradhan, Shri Pabitra Mohan
Raghavji, Shri
Rai, Shri Gauri Shankar
Ram, Shri R. D.
Ramachandran, Shri P.
Ramjiwan Singh, Shri
Saeed Murtaza, Shri
Sai, Shri Larang
Saran, Shri Daulat Ram
Sheo Narain, Shri
Sinha, Shri Satyendra Narayan
Tiwary, Shri D. N.
Tyagi, Shri Om Prakash
Varma, Shri Ravindra
Yadav, Shri Jagdambi Prasad.

*Wrongly Voted for AYES.

MR. CHAIRMAN: Subject to correction the result*** of the division is:

Ayes: 23

Noes: 33

The motion is not carried by the required majority. It is not passed.

The motion was negatived.

17.53 hrs.

ALIGARH MUSLIM UNIVERSITY (AMENDMENT) BILL

MR. CHAIRMAN: The House will now take up the next item in the agenda, the Aligarh Muslim University (Amendment) Bill.

SHRI G. M. BANATWALLA (Ponnani): Sir, I beg to move:

> "That the Bill further to amend the Aligarh Muslim University Act, 1920, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

Sir, this Bill originated in the Rajya Sabha as a Private Members' Bill, moved by the hon. Member, Shri Triloki Singh and it was passed by that House. Now I have the honour and pleasure to move in this august House for the consideration of the Bill that has been passed by the Rajya Sabha.

Sir, I had also introduced in this House an identical Bill, which of course aimed at the amendment of the Constitution. That Bill became a victim of procedural difficulties and could not come up for discussion. In the meantime, the Rajya Sabha has passed this Bill. I have come before this House to move this Bill, and I am sure the House will join me in passing this Bill and placing it on the statute book.

The Bill represents the strong sentiments and aspirations of Muslims who have courted arrests and even shed their blood for the restoration and legal recognition of the minority character of the University in a manner as to secure the protection of Art. 30(1) of the Constitution.

I quote this Article. Article 30(1) says:

> "All minorities, whether based on religion or language, shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice."

It is, however, most unfortunate that untenable arguments are formulated and advanced in order to deprive the Muslims of their university. It is unfortunate that such arguments are advanced that the university was never established by the Muslims that the university had no link whatsoever with the Muslims exclusively, that the Muslims never had exclusive power for administration of the university and that non-Muslims have been given admission in the university. I say that all such arguments are most unfortunate. It has been contended that from the point of view of establishment and from the point of view of administration Aligarh Muslim University has no link with any particular community exclusively. Therefore, the University cannot lay any claim to be a minority institution as envisaged by Article 30(1) of the Constitution and consequently the Muslims cannot claim to have governing powers. Such was the nature of contention made by the hon. Minister Dr. P. C. Chunder, in the Rajya Sabha when the Bill was under consideration.

***The following members are recorded their Votes:

AYES: Shri A. Sunna Sahib.

NOES: Prof. Samar Guha, Shri Shambhunath Chaturvedi and Shri Sushil Kumar Dhara.